

मुकदमों का विवरण

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

(विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2018 का डी. सं. 46699) अक्टूबर 09, 2023

[के. वी. विश्वनाथन, जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:मामला उन मामलों में उठाए जाने वाले कदमों/दिशानिर्देशों से संबंधित है जहां दोषी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर आत्मसमर्पण करने के बावजूद मामले को चैंबर में सूचीबद्ध नहीं किया गया था और संचार में चूक के कारण विशेष अनुमति याचिका को आकस्मिक रूप से खारिज कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय नियम, **2013-आदेश XXII r.5** - आपराधिक कार्यवाही में विशेष अनुमति याचिकाएं-अभियुक्त द्वारा समर्पण-संचार में चूक-प्रभाव:

आयोजित किया गया:दोषी को विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले सजा के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है जब तक कि समर्पण से छूट के लिए आवेदन नहीं किया जाता है-न्यायाधीश इन-चैंबर्स को आत्मसमर्पण करने या छूट से इनकार करने की शक्ति होती है-जब कोई न्यायाधीश इन-चैंबर आत्मसमर्पण करने के लिए समय देता है, तो अगली सुनवाई में, न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए कि क्या दोषी ने आत्मसमर्पण किया है या नहीं-यदि आत्मसमर्पण से छूट से इनकार कर दिया जाता है और आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो मामले को गैर-अभियोजन के लिए चैंबर न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए-तथ्यों पर, दोनों याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन हालांकि मामले को चैंबर में सूचीबद्ध किए जाने से पहले या उससे पहले कोई संचार नहीं आया था और संचार में चूक के कारण, विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।

83

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

सूचित किया जाता, वे समय गंवाए बिना उपचारात्मक कदम उठाते-याचिकाकर्ता संख्या 1 की याचिका को बहाल किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता संख्या 2 की याचिका को समाप्त कर दिया गया-तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये घटनाएँ फिर से न हों-इसके मद्देनजर, आगे की कार्रवाई के रूप में आवश्यक दिशानिर्देश, ऐसे मामलों में जहां आत्मसमर्पण से छूट देने से इनकार करने के बाद, जानकारी अदालत को नहीं मिल रही है-न्यायाधीश इन-चैंबर्स उन मामलों में एक

न्याय मित्र नियुक्त कर सकते हैं जहां वकील अनुपस्थित हैं-ऐसे मामलों में रजिस्ट्री ट्रायल जज से एक रिपोर्ट मांग सकती है, जो संबंधित पुलिस को उचित निर्देशों के साथ और जेल अधिकारियों को वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट कर सकते हैं-दिशानिर्देश।[पैरा 15-19,21,23,24,26,29]

सूचना और प्रौद्योगिकी-डिजिटलीकरण-दोषियों के समर्पण और अभिरक्षा विवरण के संबंध में अदालत के लिए अद्यतन जानकारी की उपलब्धता-आवश्यकता:

आयोजित किया गया:तंत्र विकसित किया जाएगा जिसके तहत जेल अधिकारी एक अनुकूलित वेब पोर्टल पर दोषियों के समर्पण और हिरासत के विवरण को आपराधिक अपील/विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंधित नंबरों के साथ अपलोड करेंगे, जैसे कि सभी अद्यतन जानकारी एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध होगी।[पैरा 30]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

मोहम्मद.सुकुर अली बनाम असम राज्य [2011] 3 एससीआर 209:(2011) 4 एससीसी

729; मदन लाल कपूर बनाम राजीव थापर और अन्य [2007] 9 एससीआर 686:(2007) 7 एससीसी 623; बानी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1996] 3 सप्लीमेंट। एससीआर 247:(1996) 4 एस. सी. सी. 720; सुक दास बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल

प्रदेश [1986] 1 एससीआर 590:(1986) 2 एस. सी. सी. 401; माधव हयावदानराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य [1979] 1 एस. सी. आर. 192:(1978) 3 एससीसी 544;

सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 2 एससीआर 557:(1980) 3 एससीसी 488 – संदर्भित किया गया।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:विशेष अवकाश याचिका (सी. आर. एल.) 2018 की डायरी No.46699।

सी. आर. ए. Nos.151 और 2014 के 188 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

85

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनामपश्चिम बंगाल राज्य 86

रूप:

अनिल कुमार, प्रदीप कुमार मित्तल, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का निर्णय/आदेश

1. इस मामले के तथ्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। याचिकाकर्ता नं. 2-याचिकाकर्ता संख्या 1-संजीत साहा के साथ अनिल साहा ने 2014 के सी. आर. ए. संख्या 188 के साथ 2014 के सी. आर. ए. संख्या 151 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक सामान्य विशेष अनुमति याचिका का नेतृत्व किया। याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत अपनी दोषसिद्धि और 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा को चुनौती दी थी और छह महीने के लिए पर्याप्त कारावास के रूप में और चूक में Rs.20,000/- की राशि का भुगतान करने के निर्देश को चुनौती दी थी।

2. विशेष अनुमति याचिकाओं का विधिवत समर्थन अनिल साहा के एक हलफनामे द्वारा किया गया था-याचिकाकर्ता नं। 2 13.12.2018 पर शपथ ली। विशेष अनुमति याचिकाओं के साथ समर्पण से छूट के लिए एक आवेदन भी था। 3. समर्पण से छूट के लिए आवेदन 01.03.2019 पर लर्नड चैंबर जज के समक्ष आया जब याचिकाकर्ताओं के वकील की उपस्थिति में निम्नलिखित आदेश दिया गया:-

“समर्पण से छूट के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

आत्मसमर्पण करने और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया जाता है।”

4. इसके बाद, यह मामला आई. डी. 1 पर लर्नड जज इन-चैंबर्स और लर्नड जज के समक्ष सुनवाई के लिए आया, यह देखने के बाद कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आत्मसमर्पण का सबूत नहीं दिया है, समर्पण प्रमाण देने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया। आदेश इंगित करता है कि नियुक्त वकील सुनवाई में उपस्थित नहीं था। यह भी आदेश दिया गया था कि यदि समर्पण प्रमाण 24.02.2020 से दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विशेष अनुमति याचिकाओं को अदालत में आगे कोई संदर्भ दिए बिना खारिज कर दिया जाना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

5. मेरे सामने आई. डी. 1 पर, एक चैंबर जज के रूप में, याचिकाकर्ता नंबर 1-संजीत साहा द्वारा दायर तीन आवेदन सुनवाई के लिए आए। एक विविध आवेदन (डायरी No.19330/2023) का नेतृत्व याचिकाकर्ता नं. 1-संजीत साहा विशेष अनुमति याचिकाओं की बहाली के साथ-साथ देरी की माफी के लिए एक आवेदन और अदालत के दिनांकित 24.02.2020 के आदेश को याद करने के लिए। आई. ए. No.113070/2023 भाषा में देरी को माफ करने के लिए था और आई. ए. No.95673/2023 अदालत के आदेश को वापस लेने के लिए था।

6. यह संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 15.03.2019 पर ही आत्मसमर्पण कर दिया था, जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 1 का संबंध है, विशेष अनुमति याचिका को बहाल कर दिया गया था। यह देखा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता नं। 1 और याचिकाकर्ता नं। 2 एफ. आई. ने एक आम विशेष

अनुमति याचिकाओं का नेतृत्व किया था और केवल याचिकाकर्ता नं।1 यह इंगित करते हुए वापस बुलाने के लिए कदम उठाए थे कि उन्होंने वास्तव में 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया है, याचिकाकर्ता नं।2.

7. सुविधा के लिए, याचिकाकर्ता संख्या 1, संजीत साहा के आवेदनों में पारित 25.09.2023 का आदेश नीचे दिया गया है: “देरी को माफ कर दिया गया।

आवेदक के नेतृत्व में समर्पण करने से छूट के लिए आवेदन न्यायाधीश के कक्ष के समक्ष 01.03.2019 पर सुनवाई के लिए आया। आवेदक को आत्मसमर्पण करने और उसके प्रमाण के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद, यह मामला आई. डी. 1 पर लर्नड जज इन-चैंबर्स के समक्ष सुनवाई के लिए आया और इस आधार पर कि समर्पण प्रमाण नहीं दिया गया था, निम्नलिखित प्रभाव वाले अधिनियम को एक आदेश पारित किया गया:-

“पर्यूस्ड ऑफिसी सीई रिपोर्ट दिनांकित 21.01.2020।

दिनांक 01.03.2019 के आदेश द्वारा, माननीय न्यायाधीश, इन-चैंबर ने समर्पण से छूट के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसी आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को आत्मसमर्पण करने और उसका सबूत पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।

समय दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अब तक याचिकाकर्ताओं के आत्मसमर्पण का सबूत नहीं दिया है।

87

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 88

याचिकाकर्ताओं के समर्पण के प्रमाण के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील को दो सप्ताह का और समय दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर विशेष अनुमति याचिका (ओं) अदालत को आगे कोई संदर्भ दिए बिना खारिज हो जाएगी।”

09.03.2020 पर या उससे पहले कोई समर्पण प्रमाण नहीं होने के कारण, एसएलपी को तुरंत खारिज कर दिया गया। अब आवेदक ने 05.05.2023 पर एक आवेदन का नेतृत्व किया है जिसमें कहा गया है कि इस न्यायालय के दिनांक 01.03.2019 के आदेश के बाद, आवेदक ने 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया और समर्पण प्रमाण तत्कालीन अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड को भेजा गया था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मसमर्पण का उक्त प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह भी कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो 24.02.2020 पर कोई उपस्थिति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 24.02.2020 दिनांकित आदेश आया था। यह आगे प्रतीत होता है कि अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड, जिसकी मूल रूप से सगाई हुई थी, का 10.04.2021 पर निधन हो गया था।

यह माना जाता है कि आवेदक के बेटे ने पूछताछ करने के बाद अब एक नए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं और नए अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के माध्यम से दिनांकित

24.02.2020 आदेश को वापस लेने और 2018 के SLP (CRL) D.No.46699 को बहाल करने के लिए वर्तमान आवेदन को दर्ज किया गया है। आवेदन को बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा जारी निरोध प्रमाण पत्र की एक प्रति द्वारा समर्थित किया जाता है, जो इंगित करता है कि 15.03.2019 पर आवेदक हिरासत में था। प्रमाण पत्र अभिरक्षा की कुल अवधि भी निर्धारित करता है जिसमें 27.04.2023 तक की अभिरक्षा भी शामिल है, जो प्रमाण पत्र की तारीख है।

चूंकि आवेदक ने इस न्यायालय के दिनांक 01.03.2019 के आदेश का पालन करते हुए 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए मैं इस आवेदन में योग्य हूँ।

आवेदक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत दोषसिद्धि और 10 साल के लिए कठोर कारावास की सजा को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका का नेतृत्व किया और छह महीने के लिए कारावास का भुगतान करने के लिए Rs.20,000/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

विशेष अनुमति याचिका का नेतृत्व याचिकाकर्ताओं-संजीत साहा और अनिल साहा की ओर से किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

2014 की आपराधिक अपील No.188 में उच्च न्यायालय दिनांकित 05.07.2018। विशेष अनुमति याचिका में दोनों याचिकाकर्ताओं ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के निर्णय पर 2014 की आपराधिक अपील संख्या 188 का नेतृत्व किया था।

आत्मसमर्पण से छूट के लिए आवेदन भी आरोपी अनिल साहा की ओर से दायर किया गया था। उक्त अभियुक्त अनिल साहा की ओर से भी 01.03.2019 का आदेश पारित किया गया था। वास्तव में विशेष अनुमति याचिका और अंतरिम आवेदनों के साथ-साथ रिफिलिंग में देरी को माफ करने के समर्थन में एफ़. आई. डी. आई. सह-याचिकाकर्ता अनिल साहा के नेतृत्व में हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त सह-याचिकाकर्ता अनिल साहा के संबंध में आत्मसमर्पण की स्थिति क्या है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वितीय फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगंज से एक रिपोर्ट माँगी जाए कि क्या उक्त अनिल साहा, जिसे सत्र मामले में उक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांकित निर्णय द्वारा दोषी ठहराया गया था (एस. टी. संख्या <आई. डी. 4) (और जिसे मूल रूप से ट्रायल जज द्वारा 12 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2014 की आपराधिक अपील <आई. डी. 2 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा 10 साल के आर. आई. में संशोधित किया गया था और साथ ही डिफॉल्ट सजा दी गई थी) ने अपनी सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्ट, रायगंज दो सप्ताह के भीतर जानकारी प्राप्त करने के लिए जिले के जेल अधीक्षक की सहायता ले सकता है।

यह देखते हुए कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आरोपी संजीत साहा ने वास्तव में 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया है और हिरासत में है, न्याय के हित के लिए आवश्यक है कि उसकी विशेष अनुमति याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाए। वास्तव में चूक केवल अनुपालन की सूचना देने में थी। आकस्मिक बर्खास्तगी केवल अनुपालन की सूचना देने में देरी के कारण होती है।

आवेदक को अनुपालन की सूचना देने में देरी के लिए पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है जो 10.04.2021 पर अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड के निधन के कारण भी होता है। इसलिए, देरी को माफ कर दिया जाता है और वापस बुलाने के लिए आवेदन की अनुमति दी जाती है। दिनांकित 24.02.2020 आदेश को याचिकाकर्ता सं. 1 संजीत साहा चिंतित हैं। एस. एल. पी. को जहां तक याचिकाकर्ता सं. 1-संजीत साहा चिंतित हैं।

89

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 90

जहां तक अभियुक्त अनिल साहा का संबंध है, मामले को आगे के निर्देशों के लिए चैंबर्स में 09.10.2023 पर सूचीबद्ध किया जाए।”

8. आज जब यह मामला उठाया गया तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, द्वितीय न्यायालय रायगंज, उत्तर दिनाजपुर की एक रिपोर्ट मेरे सामने रखी गई है। इस न्यायालय के सहायक पंजीयक को पत्र के रूप में एक रिपोर्ट भी मेरे सामने रखी गई है। पत्र इस प्रकार है:

“अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ. टी. सी., द्वितीय न्यायालय रायगंज, उत्तर दिनाजपुर

सं. 316 दिनांक, 07 अक्टूबर, 2023

से

माणिक लाल जाना

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ. टी. सी., द्वितीय न्यायालय रायगंज, उत्तर दिनाजपुर को।

सहायक पंजीयक,

भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

संदर्भ: पी. आई. डी. के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट: 196216/2023 डायरी नं. नं. 46699/2018 (SEC II B)

&

विविध आवेदन डायरी संख्या (ओं) 19330/2023 (संजीत साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) में दिनांकित 25.09.2023 आदेश के मामले में

2023 का सत्र मामला संख्या 76 (2012 का सत्र परीक्षण No.52) महोदय,

ऊपर निर्दिष्ट आदेश के अनुपालन में, मैं, सबसे विनम्रता से, निम्नलिखित रिपोर्ट सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत करता हूं जैसा कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता द्वारा निर्देशित किया गया है।

1. दोषी अनिल साहा ने इस अदालत के समक्ष 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया और रायगंज जिला सुधार गृह को भेज दिया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

पर्याप्त वाक्य।(ऑर्डर नं. इस न्यायालय का 81 दिनांकित 15.03.2019-अनुलग्नक-1)

2. दोषी अनिल साहा को रायगंज जिला सुधार गृह में 17.03.2023 तक रखा जाता है और मताधिकार की सजा के लिए 17.03.2023 पर बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बालुरघाट सुधार गृह में 26.05.2023 पर उनका निधन हो गया। (एस. पी. डी. की रिपोर्ट), बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह को सुपदी द्वारा अग्रेषित किया गया। जिला सुधार गृह, रायगंज।-संलग्नक-2)

यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दयालु अवलोकन के लिए है। संबंध में।

आपकी वफादारी से,

(माणिक लाल जाना)

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

एफ. टी. सी., दूसरा न्यायालय, रायगंज,

उत्तर दिनाजपुर "9. एक पत्र के साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, रायगंज का आदेश पत्र भी संलग्न किया गया है जो इस प्रकार है:

“सत्र मामला सं. 76/2012

81/15-03-2019:रिकॉर्ड को आत्मसमर्पण याचिका के साथ दोषियों की ओर से आज दायर याचिका के माध्यम से रखा जाता है।

गौरवान्वित। सुना है। माना जाता है। प्रस्तुत याचिका की अनुमति है। दो दोषियों संजीत साहा और अनिल साहा ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया जाए। अभिलेख के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता

द्वारा 2014 की सी. आर. ए. संख्या 151 और 2014 की सी. आर. ए. 188 में दिनांक आई. डी. 1 पर एक निर्णय पारित किया गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त दोनों नामित दोषियों को दोषी ठहराया और दोनों दोषियों को इस न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया और इस न्यायालय को दोनों दोषियों को जिला सुधार गृह, रायगंज में आत्मसमर्पण करने के बाद भेजने का भी निर्देश दिया।

91

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 92

निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर इस अदालत ने दोनों दोषियों के खिलाफ डब्ल्यू/ए जारी किया लेकिन उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद, दोनों दोषियों ने आज इस अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तदनुसार, दोनों दोषियों को हिरासत में लिया जाता है।

दोनों दोषियों संजीत साहा और अनिल साहा को तुरंत रायगंज जिला सुधार गृह भेजा जाए।

रायगंज जिला सुधार गृह के अधीक्षक को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05-07-2018 के निर्णय की प्रति के साथ इस आदेश की एक प्रति रायगंज जिला सुधार गृह को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

तदनुसार जेल वारंट जारी करें। B.C.I-I पालन करने के लिए।

एक बार में डब्ल्यू/ए याद करें।”

10. बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह के अधीक्षक के कार्यालय से एक अभिरक्षा प्रमाण पत्र भी मेरे सामने रखा गया है। अभिरक्षा प्रमाण पत्र से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता नं। 2 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण किया था और 17.03.2019 पर बालुरघाट केंद्रीय सुधार गृह में भर्ती कराया गया था।

11. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिरक्षा प्रमाणपत्र में यह टिप्पणी है कि याचिकाकर्ता नहीं। 2- अनिल साहा की मृत्यु 26.05.2023 पर हो गई है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण अंगों की रोगग्रस्त स्थिति का प्रभाव था-एक प्राकृतिक कारण। अभिरक्षा प्रमाण पत्र से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता नं। 2 अपनी मृत्यु के समय लगभग चार साल दो महीने और ग्यारह दिन की सजा काट चुके थे।

12. उपरोक्त पैरा 1 से 11 के तथ्यों से निम्नलिखित पहलू स्पष्ट रूप से सामने आते हैं:

i. सबसे पहले, इस न्यायालय के दिनांक 01.03.2019 के आदेश के पालन में और इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर, याचिकाकर्ता नं। 2 - अनिल साहा (याचिकाकर्ता नंबर 1-संजीत साहा की तरह) ने 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ii. दूसरा, याचिकाकर्ता नंबर 1-संजीत साहा ने वापस बुलाने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें कहा गया है कि आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उन्होंने अपने वकील को सूचित किया था, जो इस तथ्य सहित विभिन्न कारणों से कि वकील की मृत्यु 10.04.2021 पर हुई थी, इस अदालत को आत्मसमर्पण के तथ्य की रिपोर्ट नहीं कर सके।

iii. तीसरा, इसके परिणामस्वरूप विशेष अनुमति याचिकाओं को आकस्मिक रूप से खारिज कर दिया गया है क्योंकि दिनांकित 24.02.2020 के आदेश के दो सप्ताह के भीतर कोई समर्पण प्रमाण नहीं दिया गया था। स्थिति यह थी कि 15.03.2019 पर हिरासत में आत्मसमर्पण करने के बावजूद, संचार के अभाव में, दोनों याचिकाकर्ताओं की विशेष अनुमति याचिकाएं भी 24.02.2020 के आदेश के अनुसार खारिज कर दी गईं।

iv. अंत में, यह केवल याचिकाकर्ता सं. की विशेष अनुमति याचिका को बहाल करने का आदेश देते हुए था।¹¹ और जाँच के आदेश पर, यह सामने आया है कि याचिकाकर्ता नं. 2 वास्तव में 15.03.2019 पर आत्मसमर्पण कर दिया है।¹³ जैसा कि पहले बताया गया है, याचिकाकर्ता नंबर 1 संजीत साहा ने वापस बुलाने के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया है। उनकी विशेष अनुमति याचिका को पहले ही आदेश इन-चैंबर्स दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से बहाल कर दिया गया है। सभी संभावनाओं में, याचिकाकर्ता नंबर 2 अनिल साहा ने भी यही बताया होगा, क्योंकि वकील वही था। वकील 24.02.2020 पर जज इन-चैंबर्स के सामने मौजूद नहीं थे। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि दुर्भाग्य से वकील का भी 10.04.2021 पर निधन हो गया था।

14. याचिकाकर्ता नं. 2 – अनिल साहा का निधन आई. डी. 2 पर हो गया है और वह विशेष अनुमति द्वारा अपील के संवैधानिक उपाय का लाभ नहीं उठा पाए हैं, जिसके वे वैध रूप से हकदार थे, क्योंकि उन्होंने आई. डी. 1 पर आत्मसमर्पण किया था और इस तरह वे अपनी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के हकदार थे।

15. उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 का आदेश XXII नियम 5 निम्नानुसार है:-

“5. जहाँ याचिकाकर्ता को कारावास की सजा सुनाई गई है, वहाँ अपील की याचिका में कहा जाएगा कि क्या याचिकाकर्ता ने आत्मसमर्पण किया है और यदि उसने आत्मसमर्पण किया है तो याचिकाकर्ता, ऐसे समर्पण के प्रमाण के रूप में, उस न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति जिसमें उसने आत्मसमर्पण किया है या उस जेल के सक्षम अधिकारी की प्रमाण पत्र जिसमें वह सजा काट रहा है। केवल 93 का प्रमाणन

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 94

वकालतनामा पर जेल अधिकारियों के हस्ताक्षर को समर्पण का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जाएगा। जहाँ याचिकाकर्ता ने सजा के समक्ष समर्पण नहीं किया है, वहाँ अपील की याचिका रजिस्ट्री द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ समर्पण से छूट की मांग करने के लिए

एक आवेदन न हो। जहां अपील की याचिका के साथ समर्पण से छूट के लिए एक आवेदन है, केवल उस आवेदन को पहली बार में अदालत के समक्ष सुनवाई/आदेश के लिए पोस्ट किया जाएगा।”

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सामान्य नियम यह है कि एक दोषी को विशेष अनुमति याचिका दायर करने से पहले सजा के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है, जब तक कि समर्पण से छूट के लिए आवेदन नहीं किया जाता है।

16. आदेश 5 नियम 2 (35) के तहत, न्यायाधीश इन-चैंबर्स के पास आत्मसमर्पण करने या छूट से इनकार करने की शक्ति है। छूट से इनकार करने और आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में, मामले को गैर-अभियोजन के लिए चैंबर न्यायाधीश के समक्ष रखा जाता है। आदेश 5 नियम 2 (35) निम्नानुसार है:

ऑर्डर वी

चैंबर्स में व्यवसाय

2. निम्नलिखित मामलों के संबंध में न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कक्षों में बैठे एकल न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है।

“35. समर्पण से छूट के लिए आवेदन, बशर्ते कि समर्पण के लिए एक से अधिक अवसर न दिया जाए। इनकार करने और/या यदि अभियुक्त आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो मामले को गैर-अभियोजन के लिए चैंबर में माननीय न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए।”

17. कानूनी स्थिति यह है कि जब कोई न्यायाधीश इन-चैंबर आत्मसमर्पण करने के लिए समय देता है, तो अगली सुनवाई में न्यायाधीश को सूचित किया जाना चाहिए कि दोषी ने आत्मसमर्पण किया है या नहीं। यदि आत्मसमर्पण से छूट देने से इनकार कर दिया जाता है और आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो मामले को गैर-अभियोजन के लिए रखा जाना चाहिए। न्यायाधीश इन-चैंबर्स को इस स्पष्ट जानकारी के साथ तैनात किया जाना चाहिए कि क्या अभियुक्त ने छूट से इनकार करने के बाद आत्मसमर्पण किया है या नहीं। इस मामले में संचार अंतराल के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है कि तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

18. आगे की कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश आवश्यक हैं, ऐसे मामलों में जहां समर्पण से छूट से इनकार करने के बाद, जानकारी न्यायालय के सामने नहीं आ रही है। जानकारी असंख्य कारणों से सामने नहीं आ सकती है-वकील की गैर-उपस्थिति, वकील की मृत्यु या किसी अन्य कारण से। 19. वर्तमान मामले में, दोनों याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन जब मामला चैंबर्स में सूचीबद्ध किया गया था, तब आई. डी. 1

पर या उससे पहले कोई संचार नहीं आया था। इसके बाद, यह रिकॉर्ड में आया है कि नियुक्त वकील का भी 10.04.2021 पर निधन हो गया।

20. इस न्यायालय ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जब वकील किसी आपराधिक मामले में उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय एक न्यायमित्र नियुक्त करने के लिए बाध्य होता है। [मोहम्मद को देखें। सुकुर अली बनाम असम राज्य, (2011) 4 एस. सी. सी. 729] यह भी माना गया है कि वकील की अनुपस्थिति में मामले का फैसला नहीं किया जाना चाहिए और आपराधिक मामले को चूक के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है। [मदन लाल कपूर बनाम देखें।

राजीव थापर और अन्य, (2007) 7 एस. सी. सी. 623 और बानी सिंघंद अन्य

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1996) 4 एस. सी. सी. 720]। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राज्य की कीमत पर गरीबों और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिस पर अपराध का आरोप है, भले ही आरोपी मांग न करे। [सुक दास को देखें।

बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, (1986) 2 एस. सी. सी. 401]। माधव में

हयावदानराव होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1978) 3 एस. सी. सी. 544] एक कैदी को परामर्श देने के अधिकार को मान्यता दी गई है और अनुच्छेद 21 में इसका पता लगाया गया है। 21. चूंकि मामला सीधे अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है, इसलिए जेल अधिकारियों की ओर से एक सकारात्मक दायित्व निहित है कि वे अदालत को उनके आत्मसमर्पण और हिरासत की अवधि के बारे में जानकारी दें, भले ही दोषी ने किसी वकील को नियुक्त किया हो या नहीं।

22. एम. एच. होसकोट (ऊपर) में, यह भी माना गया है कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा स्वतंत्रता का अनिवार्य सार है। कैदियों को जेल की चार दीवारों में कैद किया जाना अक्सर बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में नहीं रहता है। यह इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में दोहराया गया है।

23. इस मामले में, जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है, जबकि आत्मसमर्पण का तथ्य हुआ था, यह केवल आत्मसमर्पण के संचार में है कि एक चूक हुई थी।

24. एक सकारात्मक दायित्व जेल अधिकारियों पर निहित है कि वे दोषी के आत्मसमर्पण के तथ्य को अदालत को सूचित करें। यह 95 प्रदान करने का एक साधन है।

संजीत साहा और ए. एन. आर. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 96

न्याय तक पहुँच, जो फिर से अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। चैंबर न्यायाधीश/न्यायालय प्राप्त जानकारी के आधार पर, उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उचित माने जाते हैं।

25. मॉडल जेल नियमावली, 2016, पैरा 8.62 में निम्नानुसार कहा गया है:- “अपीलीय आदेशों का संचार

8.62 अपील का निपटारा करने वाले आदेश की प्राप्ति पर, उसके उद्देश्य को अधीक्षक की उपस्थिति में संबंधित कैदी को सूचित किया जाएगा, जो आदेश पर इस आशय का प्रमाण दर्ज करेगा कि यह इस तरह से सूचित किया गया है। जब भी किसी कैदी को उसकी अपील पर आदेश प्राप्त होने से पहले स्थानांतरित किया जाता है, तो ऐसे आदेश बिना किसी देरी के उस जेल के अधीक्षक को भेजे जाएंगे, जिसमें कैदी को रखा गया है।”

26. अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे याचिकाकर्ता हिरासतमे अछि मुदा जेल अधिकारीसभ द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सभ) कें आकस्मिक रूपसँ खारिज करबाक जानकारी नहि देल गेल छल। यदि जेल अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को विशेष अनुमति याचिकाओं की आकस्मिक बर्खास्तगी के बारे में भी सूचित किया गया होता, तो उन्होंने शायद समय गंवाए बिना उपचारात्मक कदम उठाए होते। याचिकाकर्ता नंबर 1-संजीत साहा की याचिका को बहाल कर दिया गया है। जहाँ तक याचिकाकर्ता संख्या 2-अनिल साहा की बात है, याचिका समाप्त हो गई है। धारा 394 सी. आर. पी. सी. और/या उसके अनुरूप सिद्धांत के तहत स्वतंत्रता रिश्तेदारों के लिए आरक्षित है।

27. वर्तमान मामले में जो दुर्भाग्यपूर्ण परिदृश्य हुआ है, उसकी पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए। एक विकल्प रजिस्ट्री के लिए उन मामलों में हो सकता है जहां समर्पण प्रमाण वकील के नेतृत्व में नहीं है और इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि दोषी ने आत्मसमर्पण किया है या नहीं (आत्मसमर्पण करने के लिए समय दिए जाने के बावजूद), परीक्षण न्यायाधीश से एक रिपोर्ट मांगने के लिए। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश इन-चैंबर्स उन मामलों में एक न्यायमित्र नियुक्त कर सकते हैं जहां वकील रजिस्ट्री और ट्रायल कोर्ट के साथ समन्वय करने के लिए अनुपस्थित है ताकि समर्पण के तथ्य के संबंध में वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके।

28. सुनील बत्रा (द्वितीय) बनाम दिल्ली प्रशासन, (1980) 3 एस. सी. सी. 488 से एक संकेत लिया जा सकता है जिसमें कृष्णा अय्यर, जे. ने पैरा 78 (3) में निम्नलिखित दर्ज किया है:-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

“78 (3) जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित वकीलों को अनुशासन और सुरक्षा संबंधी विचारों के अधीन कैदियों के साथ साक्षात्कार, यात्रा और गोपनीय संचार के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी जड़ें मुलाकाती और पर्यवेक्षी न्यायिक भूमिका में हैं। इस प्रकार नामित वकील समय-समय पर दौरा करने और संबंधित अदालत के परिणामों को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए बाध्य होंगे जो कानूनी शिकायतों के लिए प्रासंगिक हैं।” 29. भले ही किसी भी कारण से पक्ष या वकील द्वारा अनुपालन की सूचना देने में चूक हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत संवैधानिक उपचार या वैधानिक अपील के माध्यम से उपचार के अधिकार को पराजित नहीं किया जाना चाहिए। ट्रायल जज, वर्तमान मामले की तरह, संबंधित पुलिस और जेल अधिकारियों को उचित निर्देशों के साथ वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट कर सकता है। ट्रायल जज जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डी. एल. एस. ए.) और जेलों के

ड्यूटी काउंसल की सेवाओं का लाभ उठा सकता है। जानकारी के लिए बुलाने से यह भी सुनिश्चित होगा कि यदि दोषी ने आत्मसमर्पण नहीं किया है और आत्मसमर्पण से बच रहा है, तो दोषी को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

30. दीर्घकालिक विकल्प डिजिटल युग में एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिसके तहत जेल अधिकारियों को एक अनुकूलित वेब पोर्टल पर दोषियों के समर्पण और हिरासत के विवरण को आपराधिक अपीलों/विशेष अनुमति याचिकाओं की संबंधित संख्या के साथ अपलोड करने का दायित्व होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि एक बटन के क्लिक पर, अदालत के लिए सभी अद्यतन जानकारी उपलब्ध हो।

31. इस आदेश के साथ कागजात को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

इस आदेश के साथ कागजात रखे जाएं।

निधि जैन

माननीय सी. जे. आई. के समक्ष